6.9)। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के 6.1 से 6.11 तक के पैराओं में तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा की विस्तार से चर्चा की गई है। अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में आयोजित कार्य अनुभव पर भी बल दिया गया है (नीति के पैरा 8.14)। इस प्रकार संभावित रोजगारोन्मुख शिक्षा नीति के सभी पहलू राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में पहले से ही शामिल हैं।

(ग) तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में तकनीकी शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम, देश के 542 पालिटेक्नीकों को क्षमता, गुणवत्ता और दक्षता के दृष्टिकोण से उन्नत बनाने के लिए विश्व बैंक की सहायता से चलाई जाने वाली परियोजना, प्रौद्योगिकी के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जहां त्रुटियां हों, सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, प्रौद्योगिकी के उभरते क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का सृजन आदि तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, अधिनियम, 1987 के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सांविधिक अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा शुरू किए गए प्रोन्नति संबंधी विभिन्न उपाय शामिल हैं।

Wastage of Funds by Universities in Delhi

1650. SHRI K. M. KHAN:
SHRI BISHAMBHAR NATH PANDE:

Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government have received reports regarding wastage of valuable funds made available to four Universities in Delhi;

(b) if so, the details thereof with names of such Universities;

(c) whether some lapses on the working of these Universities have also been reported; and

(d) if so, the deatils thereof and steps proposed to be taken to check the wastage of available funds?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT. OF CULTURE) (KUMARI SELJA): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the table of the Sabha.

Status of Women in the Country

1651. SHRI SANJAY DALMIA:
SHRI K. M. KHAN:

Will the Minister of HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the report on the status of women under the aegis of his Ministry had strongly deplored the inappropriate status of women in all walks of life in the country; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto and what steps Government propose to take to improve the image of women?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT) (SHRIMATI BASAVA RAJESWARI): (a) No, Sir. No status report deploring the condition of Indian women has been brought out. However, a draft country Report for the 4th World Conference on Women (Beijing 1995) has been prepared which highlights various aspects relating to thte situation of Indian Women including their problems, their challenges, their visions and their perceptions and the Government and non-Government response. This Draft Report is now being deliberated and discussed widely in the country.

(b) Continuous efforts are on to improve the status of women through advocacy, institutional and policy development, programme interventions and measures of affirmative discrimination seek-

ing to empower women socially, politically and economically.

आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना

1652. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना-वधि के दौरान माध्यमिक (मिडल) विद्यालयों में "आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना" के कार्यान्वयन संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है और उक्त योजना के प्रथम चरण में कितने विद्यालयों को शामिल किया जाएगा ;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अभी तक उक्त योजना के अधीन सातवीं कक्षा तक के प्राप्त परिणामों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या सरकार "आपरेशन ब्लैक बोर्ड की विस्तारिक योजना" के लाभों को प्राथमिकता के आधार पर देश के पिछड़े क्षेत्रों तथा महिला/बालिका शिक्षा क्षेत्रों को उपलब्ध कराने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) आठवीं योजना के दौरान, आपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना को उच्च प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ाया गया है तथा इसे 1993-94 से आरम्भ किया गया है ।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कोई राज्यवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। जिन राज्यों में मौजूदा चरण के अन्तर्गत कार्यान्वयन का कार्य पूरा हो गया है, उन राज्यों में उच्च प्राथमिक स्कूलों की कवरेज पहले चरण में आरम्भ की गई है आठवीं योजना के दौरान लगभग 14000 (10%) उच्च प्राथमिक स्कूलों को शामिल किए जाने का प्रस्ताव है ।

(ग) इस योजना को वर्ष 1993-94 से उच्च प्राथमिक स्कूलों तक बढ़ाया गया है। आपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना के कार्यान्वयन की राज्यवार प्रगति (कक्षा iv अथवा v तक के स्कूल, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के गठन के आधार पर विवरण में दी गई है **(नीचे देखिये)** ।

(घ) और (ङ) विस्तृत आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत, राज्यों को स्कूलों का चयन करते समय निम्नलिखित मानदण्ड अपनाने का परामर्श दिया गया है :-

- आठवीं योजना के दौरान, केवल ग्रामीण स्कूल ही शामिल किए जायेंगे ।
- चयन में बालिका स्कूलों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अ०ज०/अ०ज० जाति के क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी ।